सांध्य दैनिक
4PM
जिद...सच की
मूल्य ₹ 3/-
www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_SanjayS YouTube @4pm NEWS NETWORK
● वर्ष: 10 ● अंक: 331 ● पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, गुरुवार, 9 जनवरी, 2025

हमारी संपत्ति हर शाम दरवाजे से बाहर निकलती है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि वो अगली सुबह वापस आ जाए।
-एन आर नारायण मूर्ति

गुप्टिल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को कहा... 7 | यूपी की सियासत पर अफसर बन... 3 | मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग की... 2

दिल्ली विस व मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए सजने लगा मैदान

भाजपा व कांग्रेस ने भी कसी कमर

चुनाव से पहले केजरीवाल ने चला जाट आरक्षण का दांव

- » केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, धोखा देने का लगाया आरोप
- » मिल्कीपुर में साफ-सुथरा चुनाव करवाने के लिए सपा ने कसी कमर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। दिल्ली विस चुनाव व यूपी के मिल्कीपुर विस उपचुनाव के लिए मतदान की तारीखें आ चुकी हैं। तारीखों के ऐलान के साथ ही दोनों ही राज्यो में सियासी मैदान सजने लगे हैं। जहां दिल्ली में आप सरकार ने जनता के लिए चुनावी वादे करके फिर से सत्ता वापसी के संकेत देने शुरू कर दिये हैं तो भाजपा व कांग्रेस आप को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं।

इस बीच सपा, टीमएसी का साथ मिलने से आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और जोश में आ गए हैं। उन्होंने अपना सहयोग देने के लिए बंगाल की सीएम ममता बनर्जी व सपा प्रमुख अखिलेश यादव को धन्यवाद दिया है। वहीं यूपी में भी मिल्कीपुर सीट जो सपा के विधायक अवधेश प्रसाद के फैजाबाद लोस सीट से सांसद बन जाने से रिक्त हो गया था उसके उपचुनाव को लेकर भाजपा व सपा में प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। जहां सीम योगी कई बार अयोध्या कर चक्कर लगाकर इसे जीतने की जुगत कर रहें हैं वहीं सपा भी कमर कस चुकी है।

ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां दूर करे केंद्र

केजरीवाल ने लिखा, ओबीसी आरक्षण को लेकर केंद्र की नीतियों में कई विसंगतियां हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसे कि मुझे पता चला कि केंद्र की ओबीसी लिस्ट में होने की वजह से राजस्थान से आने वाले जाट समाज के युवाओं को दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के ही जाट समाज को दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि आपकी सरकार ने दिल्ली में जाट समाज को ओबीसी आरक्षण होने के बावजूद उन्हें केंद्रीय ओबीसी लिस्ट में शामिल नहीं किया है। ये तो दिल्ली के जाट समाज के साथ धोखा है।

दिल्ली
विधानसभा
चुनाव

दिल्ली के जाटों के साथ भाजपा ने किया धोखा : केजरीवाल

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जाट समुदाय को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल करने के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखा। केजरीवाल ने लिखा कि केंद्र सरकार पिछले 10 सालों से लगातार जाट समाज के साथ धोखा कर रही है। केंद्र सरकार की वादाखिलाफी की वजह से दिल्ली के ओबीसी समाज के हजारों युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। केजरीवाल ने पत्र में लिखा, एक महत्वपूर्ण विषय पर 10 साल पहले आपका किया वादा आपको याद दिलाने के लिए यह पत्र लिख रहा हूं। दिल्ली के जाट समाज के कई प्रतिनिधियों से पिछले कुछ दिनों में मुलाकात हुई। इन सभी ने केंद्र की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली के जाट समाज की अनदेखी किये जाने पर चिंता जाहिर की। जाट समाज के प्रतिनिधियों ने मुझे बताया कि आपने 26 मार्च 2015 को दिल्ली के जाट समाज के प्रतिनिधियों को अपने घर बुलाकर ये वादा किया था कि जाट समाज, जो दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में है, उसे केंद्र की ओबीसी लिस्ट में भी जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें दिल्ली में मौजूद केंद्र सरकार के कॉलेजों और नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सके।

सीएम योगी को करारा झटका

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के सीएम योगी को करारा झाटका दिया है। शीर्ष अदालत ने गैंगस्टर रहे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ में अब्बास अंसारी की जमीन पर पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए मकान बनाने की यूपी सरकार की योजना पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अब्बास अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। साथ ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि वे अब्बास अंसारी की याचिका पर जल्द सुनवाई करें। इस फैसले को यूपी की योगी सरकार को झटके के रूप में माना जा रहा है। गौरतलब है कि साल 2020 में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कुख्यात गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की जमीन को अवैध मानते हुए बुलडोजर चला दिया था।

महायुति के सहयोगियों में नहीं दूर हुई नाराजगी

- » महाराष्ट्र में सियासी उठा-पटक जारी
- » महाविकास अघाड़ी में भी मची है रार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। महाराष्ट्र में सरकार बने एक महीने से ज्यादा हो गए हैं पर वहां पर सियासी उठा-पटक अब भी जारी है। जहां महायुति सरकार में शामिल पार्टियों के नेताओं की भाजपा व सीएम देवेन्द्र फडणवीस से नाराजगी जग जाहिर है। इस बीच विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में भी रस्साकशी जारी है।

दरअसल ऐसी खबरें आ रही हैं कि जहां एनसीपी के नेता छगन भुजबल मंत्री न बनाए जाने से नाराज हैं वहीं सीएम द्वारा पूर्व शिंदे सरकार की कई योजनाओं की जांच का आदेश देने पर भी शिवसेना में भाजपा से नाराजगी चल रही हैं। हालांकि कोई भी खुलकर कुछ बोल नही रहा है।

विस चुनाव पर अब तक 63 याचिकाएं दायर

इंडिया गठबंधन के सदस्यों का दावा है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में विसंगतियों के खिलाफ महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट की विभिन्न पीठों में लगभग 63 चुनाव याचिकाएं दायर की गई हैं। कुछ याचिकाएँ पहले दायर की गई थीं, लेकिन कई मंगलवार को दायर की गईं, क्योंकि कानून द्वारा निर्धारित 45 दिन की निर्धारित अवधि जिसके भीतर चुनाव याचिकाएँ दायर की जानी चाहिए, 7 जनवरी को समाप्त हो गई। चुनाव याचिकाएं प्रक्रिया के अनुसार उम्मीदवारों द्वारा स्वयं दायर की जानी चाहिए।

पीएम मोदी की साख पर लगा बट्टा

पासपोर्ट के मामले में घटी भारत की हैसियत!

- » पिछले साल के मुकाबले 5 रैंक नीचे पहुंचा देश भारत 85वें नंबर पर
- » हेनले एंड पार्टनर्स ने प्रकाशित की रैंकिंग इंडेक्स रिपोर्ट

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। दुनिया में मोदी सरकार भारत की धाक बढ़ने का बखान बड़े जोर-शोर से करती है पर पासपोर्ट मामले में जारी रैंकिंग में साल 2025 में देश की साख को बट्टा लगा है। भारत की रैंकिंग 2024 की तुलना में 5 अंकों का नुकसान हो गया है। दरअसल, साल 2025 की पहले छह महीने के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग जारी हो गई है। इस रैंकिंग को प्रतिष्ठित संस्था हेनले एंड पार्टनर्स ने प्रकाशित किया है। बता दें कि यह इंडेक्स इस आधार पर पासपोर्ट की रैंकिंग तैयार करता है कि उस पासपोर्ट को रखने वाले बिना किसी वीजा के कितने देशों में जा सकते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक, सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट है। जिसे रखने वाले लोग दुनिया के 195 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं।

सिंगापुर के बाद जापान का दूसरा सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट

सिंगापुर के बाद दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग में जापान दूसरे नंबर पर है। जापानी पासपोर्ट के जरिए लोगों को 193 देशों की वीजा फ्री यात्रा की अनुमति मिलती है। वहीं, जापान के बाद दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और फिनलैंड संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर काबिज हैं। इन देशों के पासपोर्ट पर 192 देशों में वीजा फ्री प्रवेश की अनुमति है। आस्ट्रिया, आयरलैंड, डेनमार्क, लक्जमबर्ग, नॉर्वे, स्वीडन और नीदरलैंड के पास दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर पासपोर्ट है। ये 191 देश में वीजा फ्री एंट्री दे सकते हैं। वहीं, 190 देशों में फ्री एंट्री के साथ न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, स्विटजरलैंड, ब्रिटेन और बेल्जियम के पास पांचवां ताकतवर पासपोर्ट है।

मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग की जाए : सपा

मिल्कीपुर उपचुनाव : सपा ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, कहा- निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाए आयोग

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर विस चुनाव में भाजपा की तरफ से किसी प्रकार की बेईमानी न हों इसके लिए उसने मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग की मांग की है। सपा ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर 5 फरवरी, 2025 को मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में सभी 414 मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग की मांग की है।

पार्टी ने अनुरोध किया है कि वेबकास्टिंग लिंक को उम्मीदवारों और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाए, जिससे वे मतदान प्रक्रिया की निगरानी कर सकें और स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित कर सकें। निर्वाचन आयोग ने अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का कार्यक्रम मंगलवार को घोषित कर दिया, जिसके तहत पांच फरवरी को मतदान और आठ फरवरी को मतगणना होगी।

कांग्रेस सपा प्रत्याशी को देगी समर्थन : अजय

अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। कांग्रेस ने इस सीट पर सपा के उम्मीदवार का समर्थन किया है। इस संबंध में पार्टी नेताओं को निर्देश दे दिए गए हैं। कांग्रेस ने इसके पहले नौ सीटों पर हुए उपचुनाव में भी भाग नहीं लिया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हमने भाजपा को हराने के लिए सपा का समर्थन किया है।

लोस चुनाव में अवधेश प्रसाद की जीत के बाद खाली हुई सीट

मिल्कीपुर विधानसभा सीट 2022 में समाजवादी पार्टी (सपा) के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए अवधेश प्रसाद के 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद (अयोध्या) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी के तौर पर सांसद चुने जाने के बाद विधानसभा सीट से उनके इस्तीफा देने से रिक्त हुई है। मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान में उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर के हवाले से बताया गया कि निर्वाचन आयोग द्वारा मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार, निर्वाचन की अधिसूचना 10 जनवरी 2025 (शुक्रवार) को जारी की जाएगी।

लिस्ट में नाम कटवाकर सरकार चुनाव जीत रही है : राम भुआल

मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर हुए सवाल पर रामभुआल ने कहा कि सरकार सत्ता में बने रहने के लिए हर स्तर पर उतरकर बूथ कैपचरिंग से लेकर अपने अधिकारियों को लगाकर वोटरों को प्रभावित कर रही है। लिस्ट में नाम कटवाकर ये सरकार चुनाव जीत रही है। ये अपनी लोकप्रियता से कोई चुनाव नहीं जीत रही है।

सांसद राम भुआल निषाद मोतिगरपुर थाना क्षेत्र में पूर्व जिपं अध्यक्ष/सदस्य ओपी चौधरी के आवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद मीडिया से बात करते हुए पूर्व सांसद मेनका गांधी पर हमला बोला। सांसद ने कहा पूर्व सांसद ने किया क्या हैं, वह देखने से लग रहा है। न सड़क है, न कोई बढ़िया हॉस्पिटल है। उनकी सरकार थी लेकिन कोई रोजगार के अवसर नहीं मिले। न कोई फैक्टरी लगी न कोई खाद का कारखाना लगा। अभी बीते दिनों खाद की इतनी किल्लत थी जबकि सुल्तानपुर में किसानों की संख्या बड़ी है। खेतीबाड़ी का काम यहां ज्यादा होता है।

गरीबी व बेरोजगारी में सबसे अव्वल राज्यों में शुमार है बिहार : तेजस्वी

» बोले- 20 साल से राज्य व केंद्र में 11 साल से डबल इंजन की सरकार तब भी बेहाल है बिहार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

बक्सर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एकबार फिर बिहार सरकार व भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। श्री यादव ने कहा कि बिहार में 20 साल तो केंद्र में 11 साल से डबल इंजन की एनडीए की सरकार है। बिहार को नंबर वन राज्य बनाने की घोषणा किया गया था। लेकिन, आज नीति आयोग का रिपोर्ट देखा जाए तो गरीबी में पलायन में बेरोजगारी में सबसे अव्वल राज्यो में बिहार है। विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया गया उसे भी पूरा नहीं किया गया है।

बीपीएससी मामले छात्र आंदोलन पर सरकार को घेरते हुए कहा की कभी गांधी मैदान युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का गवाह बनता था। आज एनडीए के राज्य में नौजवानों की दुर्गति कि जा रही है। लाठी डंडे नौजवानों पर बरसाए जा रहे। हमलोगों की सरकार में आने से पहले भी पेपर लीक होता था। बिहार सरकार से जाने के बाद भी पेपरलीक हो रहा है। लेकिन, करवाई किसी पर नही हुई। मैट्रिक की परीक्षा से लेकर बीपीएससी की परीक्षा तक का पेपर लीक हो रहा है।

उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था। इसके गठन के पीछे का उद्देश्य ही लोकसभा चुनाव था। यह पहले से ही तय था। बिहार के परिपेक्ष्य में बात करें तो यहां पर विपक्ष की सभी पार्टियां शुरू से ही एकजुट है। हमलोग साथ में काम कर रहे। आगे भी करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजद के चुनाव लड़ने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे या नहीं यह फैसला राष्ट्रीय जनता दल करेगा। अब तक हमारे दल ने इस पर फैसला नहीं किया है। पार्टी की स्थिति जल्द ही स्पष्ट होने की संभावना है।

हिमाचल में राजभवन–सरकार में बढ़ा टकराव

» राज्यपाल की शब्दावली दुर्भाग्यपूर्ण : नेगी

» चुनावी वादे पूरा करना राजभवन का काम नहीं : गवर्नर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

जनजातीय विरोधी थी जयराम सरकार

मंत्री नेगी ने कहा कि पूर्व भाजपा के समय भी उन्होंने इसे लेकर आंदोलन किया था। तत्कालीन जयराम सरकार ने 2020 में एक साल के लिए एफसीए को जनजातीय क्षेत्र में नौतोड़ को निलंबित किया था, लेकिन इसमें केवल एक ही व्यक्ति को फायदा पहुंचाया गया। वह जनजातीय लोगों के विरोधी हैं। जब वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे, तब भी इस कानून को सस्पेंड किया था। किन्नौर में 500 लोगों को पट्टे मिले व 6 हजार का संयुक्त निरीक्षण हुआ था। दिसंबर 2017 में भाजपा सरकार बनी। एफसीए 2018 तक सस्पेंड था।

शिमला। राजभवन और सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा था कि किसी दल के चुनावी वादे पूरा करना राजभवन का काम नहीं है। राज्यपाल के इस बयान पर राजस्व एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्यपाल की ओर से ऐसी शब्दावली दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनावी वादे पूरा करने के लिए ही सरकार है।

प्रदेश सचिवालय में बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में नौतोड़ बहाली करना कांग्रेस सरकार का दायित्व है। सांविधानिक तरीके से मांग करना गलत नहीं है। नौतोड़ विधेयक को मंजूरी के लिए वह पांच बार राज्यपाल से मिल चुके हैं। छठी बार फिर मिलकर आग्रह करेंगे। नौतोड़ को लेकर राजभवन ने जो आपत्तियां लगाई हैं, उनमें पूरे नाम–पते का जिक्र किया गया है। इसका पूरा डाटा राजभवन को दिया जाएगा। राज्यपाल ने जो फेक शब्द का जिक्र किया है, उस पर उन्हें आपत्ति है। इसमें कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं है, न ही पहले हुई है। राज्यपाल व राजभवन का अनादर कभी नहीं किया गया है। नेगी ने कहा कि राज्यपाल नौतोड़ के मसलों की छंटनी नहीं करेंगे, उसके लिए अधिकारी बैठे हैं। राज्यपाल को एफसीए 1980 को सस्पेंड करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी तक 12,742 मामले लंबित हैं। जनजातीय क्षेत्र के जिन लोगों के पास 20 बीघा से कम भूमि है, उन्हें सरकार ने 20 बीघा जमीन देने का नौतोड़ नियम में प्रावधान किया है। नौतोड़ के लिए कभी भी आवेदन कर सकते हैं।

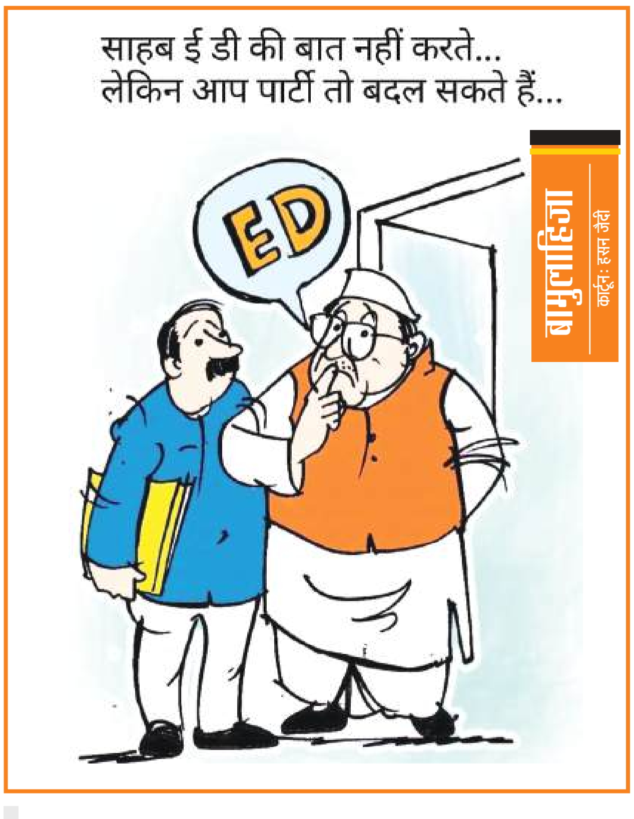
साहब ई डी की बात नहीं करते...
लेकिन आप पार्टी तो बदल सकते हैं...
ED
बामुलाहिज़ा
कार्टून : हसन जैदी

एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी की बैठक, सत्ता पक्ष व विपक्ष में तकरार

» जेपीसी सदस्यों को सूटकेस में सौंपी गई 18 हजार पन्नों की रिपोर्ट

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। एक राष्ट्र एक चुनाव पर दो विधेयकों की जांच के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी पहली बैठक की। जहां भाजपा सांसदों ने विधेयकों को देश के लिए जरूरी बताया, वहीं विपक्षी सदस्यों ने विधेयकों की आलोचना करते हुए दावा किया कि ये राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन करेंगे। पहली बैठक के दौरान कानून मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को राम नाथ कोविंद समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी।

अधिकारियों ने कथित तौर पर सदस्यों को प्रस्तावित विधेयकों के प्रावधानों के बारे में भी बताया। इस बैठक में समिति के सदस्यों को एक बड़े सूटकेस में 18,000 पन्नों से अधिक दस्तावेज़ सौंपे गए।

कितनी ईवीएम की जरूरत होगी बताए सरकार : प्रियंका

बैठक के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की संख्या पर सवाल उठाया। कांग्रेस सांसद ने सवाल किया कि क्या एक साथ चुनाव आर्थिक रूप से व्यवहार्य होगा और एक बार में मतदान के लिए कितनी ईवीएम की आवश्यकता होगी। प्रियंका ने दावा किया कि सरकार द्वारा बताए गए खर्च के आंकड़े 2004 में पहली बार ईवीएम लागू होने से पहले के हैं।

R3M EVENTS
ACTIVATION · EVENTS · EXHIBITION
R3M EVENTS
4/725 Vaibhav Khand, Gomti Nagar, Lucknow
E-mail: rajendra@r3mevents.com, Mob : 095406 11100

यूपी की सियासत पर अफसर बन रहे आफत!

भाजपा के विधायक भी जता रहे हत्या का अंदेशा

सरकार के कैबिनेट मंत्री लगा रहें एसटीएफ पर आरोप

- सीएम की चुप्पी पर उठ रहे सवाल
- विपक्ष ने साधा भाजपा व योगी सरकार पर निशाना

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। यूपी में जहां योगी सरकार महाकुंभ के आयोजन में जुटी हुई है तो वहीं उसके एक सहयोगी दल के नेता व राज्य के कैबिनेट मंत्री ने प्रदेश की अफरशाही पर बड़ा आरोप लगा दिया है। आरोप इतना बड़ा था कि बकायदा प्रेस कॉफ्रेंस करके सरकार पर हमला बोला गया। सहयोगी तो सहयोगी हैं भाजपा के विधायक भी कुछ ऐसा ही दावा करते नजर आ रहे हैं। योगी सरकार के मंत्री आशीष पटेल और लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने यूपी के अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मंत्री पर लगे आरोपों को लेकर विपक्ष भाजपा व योगी सरकार पर हमलावर है।

विपक्ष ने प्रदेश के सीएम से मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर रहा है। उधर आशीष पटेल ने जहां एसटीएफ को सीने पर गोली मारने की चुनौती दी है, वहीं गुर्जर का दावा है कि उनकी हत्या के लिए 9 पिस्टल खरीदे जा चुके हैं। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार अब विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुट गई है। लेकिन इससे पहले योगी सरकार सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई है। कैबिनेट मंत्री से लेकर बीजेपी विधायक तक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने अति गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी हत्या होने की आशंका भी जाहिर कर दी है। विपक्षी दल आरोप दावे के साथ कह रहे हैं कि यूपी में अफसरशाही योगी सरकार पर पूरी तरह से हावी हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि राज्यपाल इन आरोपों की जांच कराने के लिए एक सर्वदलीय विधानसभा सदस्यों की कमेटी बनाए। बिना इसके निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है क्योंकि जिनपर आरोप लग रहा है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी अधिकारियों में से एक हैं।

यूपी एसटीएफ पर हमलावर मंत्री आशीष पटेल

दरअसल यूपी के कैबिनेट मंत्री और अपना दल एस नेता आशीष पटेल के विभाग में हुए प्रमोशन में सपा विधायक पल्लवी पटेल ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। पल्लवी के इन आरोपों को लेकर आशीष पटेल ने यूपी के सूचना विभाग पर जोरदार हमला बोला है। कैबिनेट मंत्री ने सूचना निदेशक और मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही यूपी एसटीएफ पर भी मंत्री ने हमला बोला है। आशीष पटेल ने अपने एक बयान में एसटीएफ को चुनौती देते हुए कहा था कि अगर हिम्मत हो तो मेरे सीने पर गोली मारो। फिलहाल पल्लवी पटेल ने राज्यपाल से मुलाकात कर इस मामले में स्ढ्ढश्व से जांच कराने की मांग की है।

यूपी में सभी इंजन आपस में टकरा रहे : कांग्रेस

कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि यूपी में सभी इंजन आपस में टकरा रहे हैं। सरकार के कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री के करीबी अधिकारी का नाम लेकर सीएम योगी पर निशाना साध रहे हैं। आखिर प्रदेश में चल क्या रहा है। आज भ्रष्टाचार सरकार के ऊपर सर च?कर बोल रहा है। सीएम योगी प्रशासनिक मशीनरी संभाल पाने और मंत्रियों की कार्यशैली को नियंत्रण करने में पूरी तरह से फेल हो गए हैं। प्रदेश की जनता अपने आपको ठगा महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक विपक्ष अधिकारियों पर आरोप लगाता था लेकिन अब तो विधायक मंत्री अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं। इसकी गहन जांच होनी चाहिए। अंशु अवस्थी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से विधानसभा सदस्यों की एक सर्वदलीय कमेटी बनाकर इन आरोपों की जांच कराने की मांग की है। वरना निष्पक्ष जांच हो पाना मुश्किल है।

जो अपराधी होगा उसे ही एसटीएफ से डर लगेगा : पल्लवी पटेल

पल्लवी पटेल ने एक बार फिर आशीष पटेल पर हमला बोलते हुए कहा कि जो अपराधी होगा उसे ही एसटीएफ से डर लगेगा। पल्लवी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि निर्वाचित महिला सदस्य के लिए आइटम शब्द का इस्तेमाल करने वाले संस्कारों की बात कैसे कर रहे हैं। क्या घर में अपनी मां-बहनों के लिए ऐसे ही शब्द इस्तेमाल करते हैं। पल्ल्वी पटेल ने कहा कि मंत्री के स्क्रिप्ट राइटर नोएडा में बैठकर घोड़ों की दौड़ में खच्चरों को दौड़ा रहे हैं। अपना दल कमेरावादी की डॉ. पल्लवी पटेल ने रविवार को मंत्री आशीष पटेल के ओएसडी रहे शिक्षक राज बहादुर पटेल के साथ प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने मंत्री पर आरोप लगाए। अब इस पूरे मामले में यूपी प्राविधिक शिक्षा सेवा संघ की एंट्री हो गई है। संघ ने आरोप लगाया कि अयोग्य लोग प्रमोशन का विरोध कर रहे हैं। पल्लवी पटेल ने कहा कि राज बहादुर पटेल ने प्राविधिक शिक्षा विभाग में ओएसडी के पद पर काम किया है। जब से नियम विरुद्ध डीपीसी की कार्रवाई शुरू हुई ये तब से उसका विरोध कर रहे हैं। जब विरोध के बाद भी इनकी नहीं सुनी गई तो इन्होंने ओएसडी के पद से इस्तीफा दे दिया। इनके पास मौका था, ये भ्रष्टाचार का हिस्सा बन सकते थे। विरोध के चलते राज बहादुर के परिवार को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। चुप रहने को बोला जा रहा है। एक जनवरी को कारण बताओ नोटिस देने के बाद उनका तबादला रामपुर कर दिया गया। इसके बाद भी वह सच के साथ खड़े हैं। सरदार पटेल के असली वंशज हैं। पल्लवी ने कहा कि वह बीजेपी सरकार को चुनौती दे रही हैं कि अगर सरदार पटेल के वंशजों को परेशान किया गया तो हम सड़कों पर उतरेंगे।

सत्ता की रस्साकसी में जनता पिस रही : अखिलेश यादव

बीजेपी विधायक गुर्जर के बयान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव भी योगी सरकार पर हमला बोल चुके हैं। अपने ङ्ग हैंडल पर उन्होंने लिखा है– उप्र भाजपा सरकार में दो राजधानियों के बीच आपस में ही आरोपों की तलवारें खिंचीं हैं। किसी भाजपाई मंत्री के या किसी भाजपाई विधायक के ही कंधे पर बंदूक रखकर, कोई भाजपाई ही कहीं दूर से निशाना साध रहा है। सत्ता की इस रस्साकशी में जनता और सरकारी कामकाज पिस रहा है। अधिकारी इनके घर्षण की आग में अपनी रोटी सेंक रहे हैं। दरअसल ये जो लड़ाई है, उसका कारण भ्रष्टाचार की कमाई है, जिस पर सब एकाधिकार जमाना चाहते हैं।

हमारी हत्या कराने की ताकत है उनके पास : गुर्जर

लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भी अपने बयानों से योगी सरकार को मुश्किलों में डाल दिया है। गुर्जर का कहना है कि आज हम दुखी है कि हमारी सरकार में प्रति दिन 50 हजार गाय कट रही है। अधिकारी पैसा खा रहे हैं, चारों तरफ लूट मची है। इन सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं। कमिश्नर साहब बार-बार कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते रहते हैं। वो हमारी हत्या करा दें, उनके पास इतनी ताकत है। जो बात हम बोल रहे हैं, इसपर हमारी हत्या करा सकते हैं। उसकी तैयारी भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि 25 पिस्टम 9एमएम की खरीदी जा चुकी है।

आशीष पटेल को बर्खास्त करें सीएम योगी : अजय राय

इस मामले को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अजय राय ने कहा कि बीजेपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने अगर भ्रष्टाचार किया है तो सीएम योगी को हिम्मत दिखाते हुए उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए।अजय राय ने कहा कि यूपी में जब से योगी सरकार आई है, तब से नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है, जिससे प्रदेश की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। इससे ब?ा सबूत और क्या हो सकता है कि सरकार में मंत्री आशीष पटेल की रिश्तेदार और विधायिका पल्लवी पटेल ने उनके ऊपर तमाम तथ्यों के साथ दावा करते हुए आरोप लगाया है। लेकिन मुख्यमंत्री ना तो उनकी जांच कराने को तैयार हैं और ना ही मंत्री को बर्खास्त कर पा रहे हैं। जबकि मंत्री ने सीधे-सीधे सीएम योगी के दो खास सिपहसालार एसटीएफ चीफ अमिताभ यश और सूचना निदेशक शिशिर सिंह पर खुले आम आरोप लगाया है।इसके साथ ही अजय राय ने कहा कि इस सरकार ने अपने मंत्रियों को भी डरा कर रखा है। पहली बार किसी मंत्री ने ऐसे आरोप अपनी ही सरकार में लगाये होंगे। अजय राय कहा कि एसटीएफ से केवल फर्जी एनकाउंटर और हत्याएं ही नहीं कराई जा रही है, बल्कि अपने स्ञ्जस्न के जरिये मंत्रियों को भी डराया जा रहा है।साथ ही उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत यूपी में 31 हजार 3 सौ 3 करो? के घोटाले की एक जनहित याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दायर की गई है। उन्होंने बताया कि याचिका में आरोप लगाया गया है कि जलजीवन मिशन के तहत नियम कानून को ताक पर रखकर हजारों करो? की बंदरबांट किया गया है। अजय राय ने कहा कि राम मंदिर से शुरू हुआ भ्रष्टाचार बनारस काशी कॉरिडोर होते हुए कुंभ मेले में भी पहुंच गया है। इन सभी जगहों पर सारे ठेके गुजरातियों को दिये गये हैं जो कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। जो लोग आजादी के पहले से कुंभ का कार्य किया करते थे वह आज पेटी ठेकेदारों के रूप में कार्य कर रहे हैं।शनिवार को लखनऊ प्रदेश कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेस के दौरान अजय राय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी की ह्वटीम है। 2014 में मोदी को जिताने के लिए केजरीवाल बनारस आ गए थे। केजरीवाल बीजेपी के साथ मिलकर काम करते हैं। जहां बीजेपी आगे नहीं ब? पाती वहां बीजेपी केजरीवाल को आगे ले जाती है। अरविंद केजरीवाल पहले पूरी तरह से ऋस्स् के साथ जु? हुए थे।

जिद... सच की

Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

बच्चों की स्क्रीनिंग टाइम पर लगे लगाम !

पूरी दुनिया में इस समय बच्चों की स्क्रीनिंग टाइम अर्थात मोबाइल व इंटरनेट देखने के समय के निर्धारण पर चर्चा हो रही है। ऑस्ट्रेलिया व कुछ यूरोपीय देशों ने बकायदा इस पर कानून बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत में बच्चों के लिए कुछ नियम कानून बनाने की मांग उठ रही है। समयानुकूल ये मांग उचित भी है। पिछले दो-तीन साल से भारत के पांच वर्ष से अठारह वर्ष के बच्चों में मोबाइल, इंटरनेट एवं टेक्नोलॉजी एडिक्शन बढ़ रही है, जिनमें स्मार्ट फोन, स्मार्ट वॉच, टैब, लैपटॉप आदि सभी शामिल हैं। यह समस्या केवल भारत की नहीं, बल्कि दुनिया के हर देश की है। डिजिटल होते बच्चों पर बढ़ते खतरे चिन्ता का बड़ा कारण बन रहे हैं। बच्चों के स्क्रीन पर बहुत अधिक समय बिताने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं तो बढ़ ही रही हैं, बच्चे अलगाववादी, हिंसक एवं अस्वस्थ गतिहीन जीवनशैली के अंग बनते जा रहे हैं।

छोटी अवस्था में बच्चे अधिक समय ऑनलाइन बिताने के कारण साइबरबुलिंग, ऑनलाइन शिकारियों और अन्य जोखिमों के शिकार भी हो रहे हैं। सोशल मीडिया बच्चों एवं युवाओं के संवाद का जैसे-जैसे अभिन्न माध्यम बन रहा है, वैसे-वैसे तमाम तरह के जोखिम एवं खतरे भी जुड़ते जा रहे हैं, जिनसे बच्चों एवं किशोरों को बचाने के लिये भारत में वर्ष 2023 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, इस एक्ट के नियमों के तहत नाबालिगों के लिये सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिये माता-पिता या अभिभावकों की सहमति अनिवार्य है। निश्चिय ही यह बच्चों पर बढ़रहे खतरों से सुरक्षा देने के लिये एक प्रभावी एवं सराहनीय कदम है। इंटरनेट की यह आभासी दुनिया ना जाने और कितने मासूम व छोटे बच्चों को अपने जाल में फंसाएगी और उनका जीवन तबाह करेगी? बच्चों के इंटरनेट उपयोग पर निगरानी व उन्हें उसके उपयोग की सही दिशा दिखाना बेहद जरूरी है। यदि मोबाइल की स्क्रिन और अंगुलियों के बीच सिमटते बच्चों के बचपन को बचाना है, तो एक बार फिर से उन्हें मिट्टी से जुड़े खेल, दिन भर धमा-चौकड़ी मचाने वाले और शरारतों वाली बचपन की ओर ले जाना होगा। ऐसा करने से उन्हें भी खुशी मिलेगी और वे तथाकथित इंटरनेट से जुड़े खतरों से दूर होते चले जाएंगे। इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग की वजह से साइबर अपराधों की संख्या भी बढ़ रही है। हमारी सरकार एवं सुरक्षा एजेंसियां इन अपराधों से निपटने में विफल साबित हो रही हैं। साइबर अरेस्ट की खबरें भी अब आना आम हो गईं हैं। अब आम व खास सबकों मिलकर इस समस्या के समाधान पर विचार करना होगा।

> “
> **पिछले दो-तीन साल से भारत के पांच वर्ष से अठारह वर्ष के बच्चों में मोबाइल, इंटरनेट एवं टेक्नोलॉजी एडिक्शन बढ़ रही है, जिनमें स्मार्ट फोन, स्मार्ट वॉच, टैब, लैपटॉप आदि सभी शामिल हैं। यह समस्या केवल भारत की नहीं, बल्कि दुनिया के हर देश की है। डिजिटल होते बच्चों पर बढ़ते खतरे चिन्ता का बड़ा कारण बन रहे हैं।**

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

न्याय प्रणाली को व्यावहारिक बनाने की पहल

डॉ. सुधीर कुमार

भारतीय न्याय संहिता, 2023 एक ऐतिहासिक पहल है जिसे भारतीय दंड संहिता, 1860 को बदलने के लिए लाया गया है। यह संहिता भारतीय न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव लाने का वादा करती है। लेकिन क्या यह वास्तव में न्याय प्रणाली में क्रांति ला पाएगी? भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए राजद्रोह का अपराध परिभाषित करती थी। यह धारा उन लोगों को दंडित करती थी जो भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के खिलाफ विद्रोह या असंतोष फैलाने का प्रयास करते थे। इस कानून के आलोचकों का मानना था कि इसका अक्सर दुरुपयोग किया जाता था। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाता था। संहिता ने राजद्रोह के अपराध को निरस्त कर दिया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय न्याय संहिता ने राजद्रोह के अपराध को हटाकर उसके स्थान पर नए अपराधों को परिभाषित किया है।

ये नए अपराध देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों से संबंधित हैं। इनमें शामिल हैं लोगों के बीच फूट डालने का प्रयास, सशस्त्र विद्रोह या हिंसा को भड़काना, अलगाववादी गतिविधियां, राजद्रोह कानून के निरसन को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, यह भी महत्वपूर्ण है कि इस नए कानून का दुरुपयोग न हो। संहिता ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए दंड को कड़ा कर दिया है। इसमें बलात्कार, यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा शामिल हैं। भारतीय न्याय संहिता, 2023 में बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा बढ़ा दी गई है। साथ ही, कुछ विशेष परिस्थितियों में बलात्कार के लिए मृत्युदंड का भी प्रावधान किया गया है। यौन उत्पीड़न को गंभीर अपराध माना गया है और इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। अब घरेलू हिंसा के मामलों में पीड़ित महिलाओं को अधिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए भी कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। शादी के वादे के झांसे में फंसाकर शारीरिक संबंध बनाने पर अब तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। ये बदलाव महिलाओं को न्याय दिलाने, सशक्त बनाने और समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़ाने में मदद करेंगे और अपराधियों को कठोर सजा दिलाएंगे। संहिता ने बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई नए प्रावधान जोड़े हैं। बाल यौन शोषण के मामलों में अधिकतम सजा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा, बाल पोर्नोग्राफी को एक गंभीर अपराध माना गया है। बाल तस्करी को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। बाल तस्करों को कठोर सजा दी जाएगी। बाल श्रम और बाल विवाह को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुक्त कराए बच्चों को शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। भारत में बाल अपराधों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। यह संहिता बच्चों को अपराध और बच्चों को शोषण से बचाने में मदद करेगी। संहिता में साइबर अपराधों से निपटने के लिए कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं। बीएनएस ने साइबर अपराधों की परिभाषा को विस्तृत किया है, जिसमें हैकिंग, डेटा चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर उत्पीड़न और अन्य प्रकार के साइबर अपराध शामिल हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रकार के साइबर अपराधों को कानून के दायरे में लाया जा सके। बीएनएस ने साइबर अपराधों के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया है। इसमें लंबी जेल की सजा और भारी जुर्माना शामिल है। इसमें साइबर अपराध सिंडिकेट बनाने और चलाने के लिए दंड का प्रावधान शामिल है। बीएनएस में साइबर अपराधों की जांच के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति का प्रावधान है। इससे साइबर अपराधों की जांच में दक्षता आएगी और अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलेगी। बीएनएस में साइबर सुरक्षा के लिए उपाय करने का प्रावधान है। इसमें महत्वपूर्ण डेटा को सुरक्षित रखने, साइबर हमलों से बचाव करने और साइबर सुरक्षा जागरूकता विस्तार के उपाय शामिल हैं। संहिता में आतंकवाद से निपटने के लिए कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं।

संहिता में आतंकवाद की परिभाषा को और अधिक व्यापक बनाया गया है, जिसमें भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले सभी कार्य शामिल हैं। संहिता में साइबर आतंकवाद से निपटने के लिए भी नए प्रावधान जोड़े गए हैं। संहिता में कई ऐसे प्रावधान हैं जो न्याय प्रणाली में गति ला सकते हैं। न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के लिए लगातार अनुसंधान और विकास पर जोर दिया गया है। न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों को आधुनिक तकनीक और प्रक्रियाओं के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। जमानत की शर्तों को आसान बनाया गया है ताकि बेगुनाह लोग जेल में लंबा समय न बिताएं। निश्चित रूप से यह सकारात्मक कदम भारतीय न्याय प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद करेगा।

उत्पादकता बढ़ाने के लिए तनाव प्रबंधन जरूरी

डॉ. संजय वर्मा

इंफोसिस के संस्थापक एनआर नारायणमूर्ति के उस बयान पर देश में खूब बहस हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए युवाओं को ज्यादा समय तक जीतोड़ मेहनत करने की जरूरत है। इसके लिए हर हफ्ते न्यूनतम 70 घंटे काम करना चाहिए। पूरी दुनिया में निजी कंपनियों में कंपनी के उसूलों के साथ-साथ अधिकारियों के हर आदेश का पालन करने और जरूरत से कई गुना ज्यादा काम करने के बदले मामूली वेतनवृद्धियों और छुट्टियों में कटौती आदि के प्रश्न अक्सर विमर्श में रहते हैं। इस पर भी कंपनियों के मालिक और हुक्मरान इसे लेकर जब-तब कोई उपदेश लेकर हाजिर हो जाते हैं कि कर्मचारियों को काम कितना करना चाहिए, दबाव कितना सहना चाहिए और छुट्टियां लेते हुए जीवन और काम में संतुलन कैसे बिठाना चाहिए। इस कड़ी में अडानी समूह के चेयरमैन ने हाल ही में बयान दिया है कि यह संतुलन (वर्क-लाइफ) तब होता है, जब आप अपना पसंदीदा काम करते हैं।

बहरहाल, नौकरियों में बढ़ते तनाव और कार्य संस्कृति में बदलाव की जितनी बातें आज हमारे देश में कही-सुनी जा रही हैं, उन्हें देखते हुए कहा जा सकता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के साथ तालमेल बिठाने और दुनिया की ताकतवर कंपनियों से आगे निकलने का दबाव भारतीय कंपनियों पर काफी बढ़ गया है। इस दबाव का नतीजा है कि कभी तो इन कंपनियों के संचालक हर हफ्ते न्यूनतम 70 घंटे काम करने की जरूरत रेखांकित करते हैं, तो कभी नौकरी में तनाव की बात स्वीकार करने पर उन्हें काम से ही हटा देने का फरमान जारी कर दिया जाता है। देश-दुनिया में आज ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो राष्ट्र निर्माण के लिए जुनून की हद तक जुटने के पक्ष में हैं। यह पूरा विमर्श सिर्फ आबादी बहुल देशों में ही नहीं बल्कि अमेरिका-ब्रिटेन जैसे विकसित मुल्कों में भी ऐसी ही जुनूनी कार्य संस्कृति की मांग उठ रही है, ताकि वहां की अर्थव्यवस्थाओं का सुदृढ़ विकास हो सके और उद्योग व रोजगार क्षेत्र के संकटों को दूर किया जा सके।

कुछ ही अरसा पहले, नोएडा की एक सैलून कंपनी ने अपने कर्मचारियों के बीच कामकाजी माहौल के बीच तनाव पैदा होने संबंधी सर्वेक्षण कराया। सौ से ज्यादा कर्मचारियों ने सर्वेक्षण में स्वीकार किया कि कामकाजी दबाव के कारण वे तनाव में हैं, तो उन कर्मचारियों को नौकरी से ही निकालने का दावा किया गया। हालांकि सोशल मीडिया पर फैसले की आलोचना के मद्देनजर कंपनी ने सफाई दी कि सर्वेक्षण का मकसद कार्यस्थल पर दबावों और तनावों से जुड़ी समस्याओं को उजागर करना था। साथ ही, जिन कर्मचारियों ने तनाव की बात कही है, उन्हें तनाव-मुक्ति नीति (डि-स्ट्रेस पॉलिसी) के तहत कुछ समय आराम करने के लिए छुट्टी और अन्य सहूलियतें दी गईं, ताकि वे नई ऊर्जा से काम में जुट सकें। बहुत मुमकिन है कि नोएडा की कंपनी का सर्वेक्षण, कर्मचारियों की प्रतिक्रिया और सोशल मीडिया पर उस कंपनी के प्रति उपजा आक्रोश एक सोची-समझी प्रचार की रणनीति (पब्लिसिटी स्टंट) हो। पर यह सच है कि भारतीय कंपनियों के संचालकों में यह अवधारणा बहुत अंदर तक पैठी हुई है कि उनके देश की कार्य संस्कृति में मूलभूत बदलावों की जरूरत है ताकि वैश्विक कंपनियों से मुकाबला किया जा सके।

इस धारणा के मुताबिक भारतीय कर्मचारियों की आदत कामचोरी की होती है। वे आदतन आलसी होते हैं। देश के ज्यादातर सरकारी कार्यालयों में ये दृश्य बेहद आम रहे हैं कि कर्मचारी या तो वक्त पर दफ्तर नहीं आते या फिर पूरे दिन अपनी टेबल से गायब रहते हैं। यही वजह है कि अब ज्यादातर सरकारी कार्यालयों और सरकारी स्कूलों में उपस्थिति दर्ज करने की बायोमीट्रिक प्रणाली और कामकाज के आकलन के लिए उनके सालाना मूल्यांकन (अप्रेजल वाली) व्यवस्थाओं को लागू किया जा रहा है। बड़ी निजी कंपनियों में इससे ज्यादा सख्ती का माहौल है। कामकाज के सख्त मानकों को लागू करने के संबंध में नारायणमूर्ति के बयानों का समर्थन कई और कंपनी-प्रमुखों ने किया है। उनकी दलील रही कि नारायणमूर्ति कामकाजी माहौल की थकान नहीं, बल्कि समर्पण के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे में यदि भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाना है, तो हम पश्चिमी देशों की उस कार्य संस्कृति को अपना मानक नहीं बना, जहां हफ्ते में चार या पांच दिन या कम समय काम करना पड़ता है।

यह देखते हुए कि भारत की कार्य उत्पादकता दुनिया में सबसे कम उत्पादक देशों में एक है, हमें अपनी कार्य उत्पादकता में सुधार करने की जरूरत है। ऐसा नहीं किया गया तो हम उन पश्चिमी देशों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे, जिन्होंने बहुत अधिक प्रगति की है। सिर्फ काम को अहमियत देने और कामकाज-जीवन संतुलन को तिलांजलि देने वाले इस फॉर्मूले को ताक पर रखने वाली इस कार्य संस्कृति के समर्थकों को ऑस्ट्रेलिया जैसी व्यवस्थाएं भी नागवार गुजरती हैं जहां दफ्तर से घर आने के बाद फोन या ईमेल का जवाब देने की जरूरत राइट-टू-डिस्कनेक्ट के अधिकार के तहत महसूस नहीं की जाती। पश्चिमी देशों में कुछ अंतर और हैं। जैसे, वहां किसी भी नौकरी या व्यवसाय के तहत काम के घंटों का समायोजन इस प्रकार किया जाता है, जिससे कर्मचारी की निजी और सामाजिक जीवनशैली नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं हो। वर्क-लाइफ बैलेंस कायम रखने की नीति के अंतर्गत यूरोपीय-अमेरिकी देशों में सरकारें और निजी कंपनियां यह हिसाब-किताब भी रखती हैं कि कहीं कर्मचारी ने साल में जरूरत से कम छुट्टियां तो नहीं लीं।

पर्वतारोहियों के लिए स्वर्ग है नेपाल

The Great Drigung Kagyud Lotus Stupa

काठमांडू

नेपाल की राजधानी काठमांडू अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर देखने योग्य स्थानों में स्वयंभूनाथ मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर, दरबार स्क्वायर शामिल है। वहीं काठमांडू का यह ऐतिहासिक स्थान राजसी महलों, मंदिरों और आंगनों का संग्रह है और इसे नेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है।

इन पांच जगहों पर घूमने आते हैं पर्यटक

नेपाल, हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा देश, जहां हर कदम पर प्रकृति की बेजोड़ सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। यह देश न केवल पर्वतारोहियों के लिए स्वर्ग है, बल्कि सांस्कृतिक पर्यटकों, वन्यजीव प्रेमियों और आत्मा की शांति की खोज करने वालों के लिए भी अद्वितीय स्थान है। यहां के धार्मिक स्थलों का अनुभव हर यात्री के लिए अविस्मरणीय साबित होता है। इसलिए नेपाल की इन पांच जगहों पर पर्यटक बहुत ज्यादा घूमने के लिए आते हैं।

लुम्बिनी

लुम्बिनी, गौतम बुद्ध की जन्मस्थली, बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल है। यह सुंदर उद्यान विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है और यहां विभिन्न देशों द्वारा निर्मित स्तूप और मठ स्थित हैं। वहीं मायादेवी मंदिर मंदिर गौतम बुद्ध की माता, मायादेवी, को समर्पित है और यहां पर गौतम बुद्ध के जन्मस्थल को चिन्हित किया गया है। वहीं गोल्डन मंदिर बौद्ध मंदिर अपनी अद्वितीय वास्तुकला और सुनहरे रंग के लिए प्रसिद्ध है।

स्वयंभूनाथ (मंकी टेम्पल)

काठमांडू के पश्चिम में एक चोटी पर 3 किलोमीटर की दूरी पर स्वयंभूनाथ मंदिर स्थित है। इसे नेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह स्थल अपने अद्वितीय वास्तुकला और मनोहारी दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। पशुपतिनाथ मंदिर हिंदू धर्म का प्रमुख स्थल है और भगवान शिव को समर्पित है। बागमती नदी के किनारे स्थित यह मंदिर धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का धरोहर है। यहां का स्वयंभू स्तूप मंदिर और परिसर पर्यटकों को काफी पसंद आता है। स्वंयभू मंदिर को मंकी टेंपल के नाम से भी जाना जाता है।

पोखरा

पोखरा, नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर, अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह स्थल पर्वतारोहियों और ट्रेकर्स के लिए एक प्रमुख आधार है। यह सुंदर झील पोखरा के केंद्र में स्थित है और यहां बोटिंग का आनंद लिया जा सकता है। देव फाल झरना पोखरा का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो अपनी खूबसूरती और रहस्यमयी गुफा के लिए जाना जाता है।

पाटन

पाटन, जिसे ललितपुर भी कहा जाता है, अपनी सांस्कृतिक धरोहर और कला के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान राजसी महलों, मंदिरों और आंगनों का संग्रह है और इसे नेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इसके अलावा सरणकोट से अन्नपूर्णा और धौलागिरी पर्वत श्रृंखला का अविस्मरणीय दृश्य देखा जा सकता है। यह स्थान सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध है।

हंसना मना है

पति-पत्नी दोनों मार्किट गए, वहां पति ने एक अनजान, लड़की से कहा हेलो! पत्नी गुस्से में -बताओ ये कौन थी? पति कुछ सोचकर- ओए चुप कर, अभी उसे भी बताना है की, तुम कौन हो..!

पति- काम के लिए बाई रखे? पत्नी- नहीं चाहिए, पति- क्यों? पत्नी-तुम्हारी आदते मैं अच्छी तरह, जानती हूं भूल गए? पहले मैं भी बाई ही थी!

देवदास की तरह जान मत दो यारो, प्यार को लात मारो यारो, मेरी बात मानो यारो, ना चंद्रमुखी ना पारो, रोज़ रात एक किंगफिशर मारो, और चैन से जिंदगी गुज़ारो..!

गर्लफ्रेंड-मेरी मम्मी को तुम बहुत पसंद आये हो, पप्पू- चल पगली, कुछ भी हो मैं शादी तुमसे ही करूंगा.. आंटी से कहना वो मुझे भूल जाएं।

नजरे आज भी उस बेवकूफ को ढूंढ रही हैं, जिसने कहा था बुक के बीच में मोर पंख रखने से विद्या आती है।

30 दिन से बिना बताये घर से गायब एक राजस्थानी पति घर लौटा, पत्नी- मैं थारे गम में बीमार पड़ी थी, जै मैं मर जाती तो पति- तो मैं कोण सा श्मशान की चाबी अपणे साथ ले गया था?

कहानी

सुनहरा गोबर

एक बार की बात है, किसी शहर में एक बड़े से पेड़ पर एक पक्षी रहता था, जिसका नाम था सिन्धुक। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस पक्षी का मल सोने में बदल जाता था। यह बात किसी को भी पता नहीं थी। एक बार उस पेड़ के नीचे से एक शिकारी गुजर रहा था। शिकारी उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए ठहरा। वो आराम कर ही रहा था कि इतने में सिन्धुक पक्षी ने उसके सामने मल त्याग कर दिया। जैसे ही पक्षी का मल जमीन पर पड़ा, वो सोने में बदल गया। यह देखते ही शिकारी बहुत खुश हुआ और उसने उस पक्षी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। सिन्धुक जाल में फंस गया और शिकारी उसे अपने घर ले आया। पिंजरें में बंद सिन्धुक को देख शिकारी को चिंता सताने लगी कि अगर राजा को इस बारे में पता चला, तो वो न सिर्फ सिन्धुक को दरबार में पेश करने को कहेंगे बल्कि मुझे भी सजा देंगे। यह सोचकर, डर के मारे शिकारी ने खुद ही सिन्धुक को राज दरबार में पेश कर राजा को सारी बात बताई। राजा ने आदेश दिया कि सिन्धुक को सावधानी से रखा जाए और उसे अच्छे से खाना खिलाया जाए। ये सब सुनने के बाद मंत्री ने राजा को कहा कि आप इस बेवकूफ शिकारी की बात पर भरोसा मत कीजिये। कभी ऐसा होता है क्या कि कोई पक्षी सोने का मल त्याग करे। इसलिए, अच्छा होगा कि इसे आजाद करने का आदेश दें। मंत्री की बात सुनकर राजा ने चिड़िया को आजाद करने का आदेश दिया। सिन्धुक उड़ते-उड़ते राजा के दरवाजे पर सोने का मल त्याग करके गया। यह देखते ही राजा ने मंत्रियों को उसे पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन तब तक वो पक्षी उड़ चुका था। उड़ते-उड़ते सिन्धुक कह गया कि मैं बेवकूफ था, जो शिकारी के सामने मल त्याग किया, शिकारी बेवकूफ था, जो मुझे राजा के पास ले गया, राजा बेवकूफ था, जो मंत्री की बात में आ गया। सभी बेवकूफ एक जगह ही हैं।

कहानी से सीख: कभी भी दूसरे की बातों में नहीं आना चाहिए और अपने दिमाग से काम लेना चाहिए।

7 अंतर खोजें

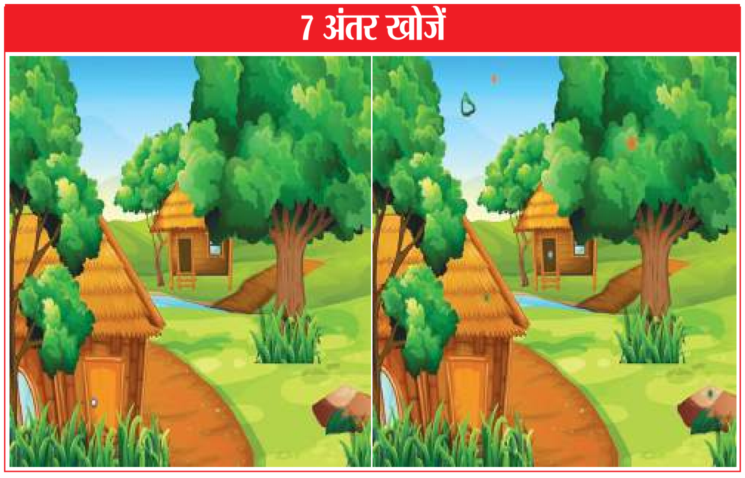

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

पंडित संदीप
आत्रेय शास्त्री

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष आज निवेश में सोच-समझकर हाथ डालें। लाभ होगा। भाग्य की अनुकूलता रहेगी। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। कोर्ट व कचहरी के काम से छुटकारा मिल सकता है।

वृषभ कारोबार में लंबे समय से रुके कार्य पूर्ण होने के योग हैं। बड़ा लाभ हो सकता है। बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल रहेंगे। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे।

मिथुन नौकरी में कोई नया काम कर पाएंगे। स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद प्राप्त हो सकता है। निवेश में जल्दबाजी न करें। व्यापार-व्यवसाय ठीक चलेगा।

कर्क आय होगी। व्यापार-व्यवसाय ठीक चलेगा। नौकरी में कार्यभार रहेगा। पुराना रोग उभर सकता है। बेवजह नकारात्मकता रहेगी। आलस्य हावी रहेगा। वाणी पर नियंत्रण रखें।

सिंह कारोबार में वृद्धि होगी। नौकरी में उच्चाधिकारी की प्रसन्नता प्राप्त होगी। कोई बड़ा काम करने का मन बनेगा। वरिष्ठ व्यक्तियों का मार्गदर्शन लाभ में वृद्धि करेगा।

कन्या व्यापार-व्यवसाय मनोनुकूल लाभदायक रहेगा। उत्साहवर्धक सूचना प्राप्त होगी। भूले-बिसरे साथियों से मुलाकात होगी। व्यय होगा। विवाद को बढ़ावा न दें।

तुला व्यापारिक यात्रा सफल रहेगी। कोई बड़ा काम हो सकता है। भेंट व उपहार की प्राप्ति हो सकती है। बेरोजगारी दूर करने के प्रयास सफल रहेंगे।

वृश्चिक परिवार के साथ जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होगा। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। व्यवसाय ठीक चलेगा। व्ययवृद्धि होगी। विवाद को बढ़ावा न दें।

धनु आज आपको पत्नी के भाग्य का साथ मिलेगा। रुका हुआ पैसा मिलने के योग हैं। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। राजकीय सहयोग मिलेगा।

मकर लंबे समय से रुके कार्य पूर्ण होने के योग हैं, प्रयास करते रहें। आय में वृद्धि होगी। मित्रों का सहयोग कर पाएंगे। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा।

कुम्भ व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा। पार्टनरों से सहयोग प्राप्त होगा। निवेश लाभदायक रहेगा। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी।

मीन व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा। चोट व दुर्घटना से हानि हो सकती है। भ्रम की स्थिति बन सकती है। किसी व्यक्ति के व्यवहार से मन को ठेस पहुंच सकती है।

बॉलीवुड | मन की बात

स्काई फोर्स मेकर्स पर भड़के मनोज मुंतशिर

मनोज मुंतशिर ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने जियो स्टूडियो और स्काई फोर्स के मेकर्स को लीगल एक्शन देने की धमकी भी दे डाली है। इस गाने की रिलीज से पहले मनोज ने गड़बड़ी सुधारने की चेतावनी दी है, उन्होंने ये तक कह दिया कि ऐसा नहीं हुआ तो वे कानून का सहारा लेंगे। दरअसल, स्काई फोर्स टीम ने माये गाने पर उन्हें क्रेडिट नहीं दिया, इस कारण उन्होंने ये पोस्ट किया है। जियो स्टूडियो ने आगामी गाने एक्स का टीज़र शेयर किया, जिसमें गायक बी प्राक और संगीतकार तनिष्क बागची का नाम था। इस क्लिप में मनोज का नाम नहीं था, उन्होंने टीम ने उन्हें कैप्शन में टैग किया। मनोज मुंतशिर ने लिखा, ये गाना न केवल गाया और कंपोज किया गया है बल्कि किस ऐसे इंसान ने लिखा भी है। उसने अपने खून पसीने से ये गाना तैयार किया। लेखक का नाम हटाना, बहुत बड़ा अपमान है। अगर ये तुरंत ठीक नहीं किया गया कल गाने की रिलीज में भी तो लीगल एक्शन लूंगा। ध्यान रखिए कि मेरी आवाज कानून जरूर सुनेगा। शर्म करो। स्काई फोर्स फिल्म गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को रिलीज होने वाली है। फिल्म में अक्षय कुमार और वीर पहाड़िया नजर आने वाले हैं। फिल्म में अक्षय एक एयर फोर्स ऑफिसर के किरदार में दिखाई देने वाले हैं। वीर ने इसमें एक सहायक आईएएफ ऑफिसर की भूमिका निभाई है। इसमें सारा अली खान ने वीर की पत्नी का किरदार निभाया है। फिल्म में निमृत कौर भी नजर आने वाली हैं।

आशिकी 3 से बाहर हुई तृप्ति, पोस्टपोन हुई फिल्म

बॉलीवुड | मसाला

कार्तिक आर्यन अपनी फिल्मों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। वो फिल्म आशिकी 3 में नजर आने वाले हैं। फिल्म को अनुराग बसु डायरेक्ट करेंगे। फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद एनिमल फेम एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी को फीमेल लीड के लिए कास्ट किया गया था। फिल्म की शूटिंग इसी साल शुरू होनी थी। लेकिन अब स्टोरी में ट्विस्ट आ गया है।

मिड-डे की रिपोर्ट के अनुसार, तृप्ति डिमरी अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हैं। वो फिल्म से बाहर हो गई हैं। अनुराग बसु एक पूरी तरह से नई लव स्टोरी बनाने के लिए तैयार हैं। मिड-डे ने सोर्स के हवाले से लिखा, तृप्ति इस रोमांटिक फिल्म में काम करने को लेकर एक्साइटेड थीं। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। आशिकी 3 टाइटल रिलेटेड विवाद से गुजर रही है। इसलिए, इसे अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है।

बता दें कि ऐसी खबरें थीं कि तृप्ति ने कथित तौर पर पिछले साल फिल्म के लिए कुछ दिनों की शूटिंग की थी। ये एक मुहूर्त शॉट होना था। फिल्म से तृप्ति डिमरी के बाहर होने के पीछे के कारणों के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। आशिकी 3 की जब अनाउंसमेंट हुई थी तो बहुत चर्चा हुई थी।

इस फिल्म को भूषण कुमार और मुकेश भट्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन प्रोड्यूसर्स के बीच कुछ मतभेद की वजह से अभी बात आगे नहीं बढ़ी है। बता दें कि फिल्म के अपडेट्स को लेकर अभी तक कुछ भी ऑफिशियली सामने नहीं आया है।

इन फिल्मों में दिखीं तृप्ति डिमरी

वर्कफ्रंट की बात करें तो तृप्ति डिमरी कला,लैला मजनू, बुलबुल जैसी फिल्में कर चुकी हैं। उन्हें फिल्म एनिमल से फेम मिला था। एनिमल में वो कैमियो रोल में थीं। लेकिन उनका रोल काफी पसंद किया गया था। फिल्म में तृप्ति ने बोल्ड सीन दिए थे। इसके बाद वो बैड न्यूज, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, भूल भुलैया 3 जैसी फिल्मों में दिखीं। अब वो धड़क 2 में नजर आएंगी।

बेबी जॉन के बाद जी 2 में नजर आयेंगे वामिका गब्बी

बॉलीवुड | गपशप

द ग्रेट कपिल शर्मा शो और बेबी जॉन के बाद अब वामिका गब्बी फिल्म जी2 में नजर आएंगी। इस फिल्म में एक्ट्रेस अदिवी शेष के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी। जी2 एक स्पाई-थ्रिलर फिल्म है जिसे विनय कुमार सिरिगिनेडी डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म जी2 साल 2018 की हिट गुडाचारी का सीक्वल है, जिसकी कहानी लीड एक्टर अदिवी शेष ने ही लिखी है।

जी-2 का हिस्सा बनने को लेकर वामिका गब्बी ने कहा कि वो फिल्म के लिए बेहद एक्साइटेड। एक्ट्रेस ने कहा कि ऐसे टैलेंटेड कलाकारों और क्रू के साथ काम करने में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। वामिका ने आगे कहा कि जी-2 में दर्शकों को उनका नया रूप देखने को मिलेगा जिसके लिए वे काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। वामिका गब्बी का कहना है कि ये फिल्म उनके लिए खास हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वमिका गब्बी ने अदिवी शेष के साथ फिल्म जी-2 के लिए यूरोप में शूटिंग शेड्यूल पूरा कर लिया है। फिल्म में अदिवी शेष और वामिका गब्बी के साथ बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। इसके अलावा फिल्म के कलाकारों में मुरली शर्मा, सुप्रिया यारलागड्डा और मधु शालिनी भी शामिल हैं।

फिल्म जी2 हिंदी के अलावा 4 अलग-अलग भाषाओं में रिलीज की जाएगी। इस फिल्म को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, और मलयालम भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।

वामिका गब्बी को प्राइम वीडियो सीरीज जुबली, नेटफ्लिक्स फिल्म खुफिया और सोनी लिव सीरीज चार्ली चोपड़ा एंड द मिस्ट्री ऑफ सोलंग वैली में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। वहीं हाल ही में एक्ट्रेस क्रिसमस पर रिलीज हुई फिल्म बेबी जॉन में नजर आई थीं। वरुण धवन स्टारर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पाई है। फिल्म का बजट 160 करोड़ रुपए है लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर बजट का आधा भी नहीं कमा सकी है।

अजब-गजब | **इस गांव में निभायी जाती है अनूठी परंपरा**

यहां लड़की वाले नहीं, लड़के वाले देते हैं दहेज

मध्य प्रदेश का बुरहानपुर अपने समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास और अनूठी परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहां स्थित भिलाला समाज 500 साल पुरानी एक विशेष परंपरा को आज भी जीवंत रखे हुए हैं। आमतौर पर जहां भारत में दहेज प्रथा के तहत दुल्हन का परिवार दूल्हे वालों को दहेज देता है, वहीं भिलाला समाज में यह परंपरा उल्टी है। यहां दूल्हे का परिवार दुल्हन के परिवार को दहेज देता है। भिलाला समाज की यह परंपरा 500 साल पुरानी है, जो आज भी कायम है। समाज के वरिष्ठ बुजुर्ग बताते हैं कि पहले दहेज के रूप में केवल 1, 11 या 51 दिए जाते थे। लेकिन समय के साथ यह राशि बढ़कर ढाई लाख रुपए तक पहुंच गई है। दहेज की यह राशि शादी की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यदि शादी पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ होती है, तो 80,000 का दहेज दिया जाता है। वहीं, यदि लड़की अपने प्रेमी के साथ भागकर शादी करती है, तो दहेज की राशि 2.5 लाख तक बढ़ जाती है।

भिलाला समाज के बुजुर्ग रूप सिंह ने बातचीत में बताया, हमारे समाज में यह परंपरा वर्षों से चल रही है। हालांकि अब यह राशि इतनी बढ़ गई है कि कुछ परिवारों के लिए इसे जुटाना मुश्किल हो रहा है। इसे कम करने के लिए प्रदेश स्तरीय बैठकों और ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि कोई भी परिवार आर्थिक दबाव में न आए।

समाज के कुछ सदस्यों ने बताया कि दहेज की उच्च राशि के कारण कई परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि किसी के पास पर्याप्त धन नहीं होता, तो वे अपने खेत या जमीन बेचकर दहेज की राशि जुटाते हैं। यह परंपरा शादी के एक महीने बाद आयोजित पंचायत के माध्यम से पूरी होती है। पंचायत दहेज की राशि तय करती है, जिसे दूल्हे के परिवार द्वारा दुल्हन के परिवार को दिया जाता है।

दहेज की बढ़ती राशि को देखते हुए भिलाला समाज इसे कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। वर्तमान में, समाज 50,000 तक की सीमा तय करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए ग्राम सभाओं में चर्चा की जा रही है और परिवारों को जागरूक किया जा रहा है। समाज के वरिष्ठ सदस्य बताते हैं, हमारी परंपरा हमारे गौरव का प्रतीक है, लेकिन इसे समय के साथ व्यावहारिक बनाना भी जरूरी है। हमारा उद्देश्य है कि परंपरा का सम्मान बना रहे और किसी भी परिवार को आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। भिलाला समाज की यह परंपरा न केवल अपनी अनूठी पहचान को दर्शाती है, बल्कि समाज की सोच और सांस्कृतिक विविधता को भी उजागर करती है। जहां यह परंपरा महिलाओं के परिवार को आर्थिक सहारा प्रदान करती है, वहीं इसे व्यावहारिक और सुलभ बनाने के लिए समाज के प्रयास सराहनीय हैं।

इस देश में नहीं है ट्रैफिक लाइट बिना सिग्नल कैसे संभलती है भीड़?

दिल्ली हो या मुंबई, बेंगलुरु हो या कोलकाता, आजकल भारत के हर महानगर में आपको इतना ट्रैफिक मिलेगा कि लोग ट्रैफिक सिग्नलों आधे-आधे घंटे तक जाम में फंसे रह जाते हैं। भारत ही नहीं, दुनिया के बहुत से देशों में रोड पर ट्रैफिक जाम लगना आम बात है। ट्रैफिक सिग्नल इसी जाम को संचालित करने और भीड़ को संभालने के काम आता है। पर दुनिया में एक ऐसा भी देश है, जहां ट्रैफिक लाइट नहीं है। ये देश इतना अनोखा है कि अगर आप इसके बारे में जान गए, तो आप यहां पर जरूर घूमने जाएंगे। इंस्टाग्राम यूजर और ट्रैवल कपल हडसन और एमिली सोशल मीडिया पर रोचक वीडियोज पोस्ट करते हैं। हाल ही में उन्होंने एक देश का वीडियो पोस्ट किया, जहां एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। वीडियो में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी भीड़ को नियंत्रित करता दिखाई दे रहा है। इस देश का नाम भूटान है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोरा पर भी बहुत से लोगों ने पूछा कि वो कौन सा देश है, जहां ट्रैफिक लाइट नहीं है? कोरा पर लोगों ने भूटान का ही जिक्र किया, हालांकि, कुछ लोगों ने ये भी बताया कि भूटान के शहर थिम्फू में कुछ ट्रैफिक लाइट्स हैं, मगर बाकी देश में नहीं हैं। विश्वस्नीय सोर्सेज की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भूटान में एक भी ट्रैफिक लाइट्स नहीं हैं। वहीं बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भूटान की राजधानी थिम्फू में देश की एक मात्र ट्रैफिक लाइट थी, जो 24 घंटे के लिए लगी थी। उसे फिर हटा दिया गया था। अब पुलिसकर्मी ट्रैफिक को संभालते हैं, उनकी वजह से ट्रैफिक संभल जाता है। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें ट्रैफिक कर्मी भीड़ संभालता दिख रहा है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो को लाखों व्यूज मिल चुके हैं और कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक ने कहा कि भूटान कमाल का देश है। एक ने कहा कि वो तुरंत बैग पैक कर के भूटान जाएगा। एक ने कहा कि वहां पर ज्यादा कारें नहीं हैं, इस वजह से ये वहां पर मुमकिन है, जिस देश में लाखों कारें होंगी, वहां पर ये मुमकिन नहीं है।

चुनाव के समय नेता करें सिर्फ जनता के मुद्दों पर बात : प्रियंका

बिधूड़ी पर कांग्रेस महासचिव का पलटवार
बोलीं- यह सब फिजूल की हैं बातें

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी की ओर से की गई विवादित टिप्पणी पर कांग्रेस नेता और सांसद प्रियंका गांधी ने चुप्पी तोड़ी है। को प्रियंका गांधी ने बिधूड़ी के बयान को फिजूल बताया है। साथ ही बोलीं कि चुनाव के दौरान हमें दिल्ली की जनता के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। बिधूड़ी के बयान को लेकर तंज कसते हुए प्रियंका बोलीं कि कभी अपने गालों के बारे में उन्होंने बात नहीं की। यह सब बातें बेकार की हैं। साथ ही नसीहत देते हुए कहा कि चुनाव के दौरान अहम मुद्दों पर बात होनी चाहिए। बीते 5 जनवरी को भाजपा प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को लेकर विवादित बयान दिया था।

इसके बाद बिधूड़ी के बयान को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कड़ी नाराजगी जताई थी। जिसमें उन्होंने लिखा था कि यह बदतमीजी सिर्फ घटिया मानसिकता नहीं दिखाती, यह उनके अन्य सहयोगियों और सहकर्मियों की असलियत दिखाती है। कांग्रेस के हंगामे के बाद भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी ने कहा था कि मैंने कोई विवादित बयान नहीं दिया है। कांग्रेस को बयान पर एतराज है तो पहले राजद सुप्रीमो लालू यादव से कहें कि वह हेमा मालिनी से माफी मांगें। क्योंकि उन्होंने भी इस तरह का बयान दिया था। विरोध के बावजूद वह अपने बयान पर कायम हैं। रमेश बिधूड़ी ने कहा कि अगर कांग्रेस को मेरे बयान से आपत्ति है तो पहले वह लालू यादव से कहे कि वह हेमा मालिनी से माफी मांगें।

भाजपा हराओ, दिल्ली बचाओ : वृंदा करात

सीपीआई (एम) नेता वृंदा करात ने कहा कि सीपीआई (एम) दिल्ली में दो सीटों- करावल नगर और बदरपुर पर चुनाव लड़ेगी। जहां वामपंथी दल चुनाव लड़ेंगे, हम एक-दूसरे का समर्थन करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की शेष सीटों पर सीपीआई (एम) उस पार्टी का समर्थन करेगी जो भाजपा को हरा सके। मेरी पार्टी का नारा है भाजपा हराओ, दिल्ली बचाओ।

विकास और सड़कों से ज्यादा बिधूड़ी की नजर महिलाओं के गालों पर : अलका

बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के बयान को लेकर सियासी पारा काफी हाई है। कालकाजी विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने भी रमेश बिधूड़ी पर हमला बोला है। रमेश बिधूड़ी भाषा के कारण लोगों का उनसे मोहभंग हो चुका है। लोग गुस्से में हैं। विकास पर बोलिए। लेकिन विकास और सड़कों से ज्यादा आपकी नजर महिलाओं के गालों पर है। लांबा ने कहा, 'कालकाजी में कोई भी ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी पर इसका दबाव भी बना और माफी भी मांगनी पड़ी। माफी मांगने के बाद फिर दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री पर टिप्पणी कर दी। अब लोगों में काफी गुस्सा है। बीजेपी पर काफी दबाव है कि रमेश बिधूड़ी का टिकट काट दिया जाए और अगर ऐसा होगा तो यह हमारी बड़ी जीत है।' वहीं अलका लांबा ने कहा, 'मेरा सीधा मुकाबला आतिशी से है। वो विधायक और मुख्यमंत्री हैं। आतिशी ने शराब नीति का विरोध करने के बजाय उसका समर्थन किया। उनको इसका कड़े शब्दों में विरोध करना चाहिए था। लोगों में इसको लेकर भी काफी गुस्सा है।

हमने हरियाणा से छोड़ा अश्वमेघ का घोड़ा, जहां जाएगा भाजपा जीतेगी : अनिल विज

हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने दावा किया है कि दिल्ली चुनाव में भाजपा ही जीतेगी। विज ने कहा कि हमने हरियाणा में भाजपा की विजय पताका फहराकर शंखनाद कर दिया है। हमने सारे देश के अंदर अश्वमेध का घोड़ा छोड़ दिया है। जहां जहां जाएगा वहां भाजपा की विजय होगी। दिल्ली में भी भाजपा की विजय होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति की दिशा बदल दी है।

भाजपा को झटका, सनातन सेवा समिति में शामिल हुए मंदिर प्रकोष्ठ के सदस्य

आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया। भाजपा के मंदिर प्रकोष्ठ के कई सदस्य आप की सनातन सेवा समिति में शामिल हो गए हैं। आप और केजरीवाल के काम और नीतियों से प्रभावित होकर, आज बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के कई पुजारी व विद्वानजन आम आदमी पार्टी की 'सनातन सेवा समिति' में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आप नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

न्यायालय ने छोटा इमामबाड़ा से अतिक्रमण हटाने का दिया आदेश

» वरिष्ठ अधिवक्ता हैदर ने दाखिल की थी जनहित याचिका

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता सय्यद मोहम्मद हैदर रिजवी के द्वारा दाखिल की गयी जनहित याचिका में जिला प्रशासन एवं अन्य प्राधिकारियों से लखनऊ के छोटा इमामबाड़ा के दोनों (बैरूनी एवं पूर्वी गेटों) से अतिक्रमण हटवाना सुनिश्चित करने का आदेश पारित किया गया। न्यायालय ने साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वे को इन दोनों गेटों का सर्वे कर दोनों गेटों के संरक्षण में आने वाले व्यय का एस्टीमेट विलंबतम 2 सप्ताह में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है, जिससे न्यायालय उक्त गेटों के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु वांछित बजट व्यवस्था बनाई जा सके।

हैदर का सुझाव था कि उक्त मरम्मती कार्य केवल भारतीय पुरातत्व सर्वे के माध्यम से ही करवाए जाने चाहिए जिससे उक्त कार्य गुणवत्ता पूर्ण हो सकें जिससे उक्त ऐतिहारिक घरोहरें वास्तविक रूप से संरक्षित रह सकें। मुकदमे की सुनवाई के दौरान हुसैनाबाद ट्रस्ट के द्वारा प्रतिवर्ष होने वाले आय का विवरण भी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार उक्त ट्रस्ट की कमाई यद्यपि करोड़ों में है, तथापि, उसके द्वारा इमारतों का रखरखाव नहीं कराया जाता है जिसके अभाव में ये सांस्कृतिक विरासतें जीर्ण शीर्ण हो रही हैं।

डकैती का पर्याय बन चुकी है बीजेपी: पटवारी

» पीसीसी चीफ बोले- पूर्व विधायक के घर मिले करोड़ों रुपए और सोना

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

भोपाल। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार को जम कर घेरा। उन्होने कहा कि बीजेपी बोलो या करप्शन बोलो, भाजपा हर तरीके के भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है। एक क्लर्क ने 80 करोड़ रुपए का गबन कर दिया। यह ग्वालियर चंबल की घटना है। सौरभ शर्मा एक कॉन्स्टेबल था उसने किस हद दर्जे का करप्शन किया, किसके लिए किया यह बात पब्लिक डोमैन में स्पष्ट हो चुकी है। इनकम टैक्स की छापेमारी में पूर्व विधायक हरवंश राठौर के यहां से करोड़ों रुपए की नकदी, सोना और संपत्ति मिलने के मामले पर बीजेपी को घेरा है।

पटवारी ने अजमेर दरगाह पर चादर भेजने से पहले भोपाल में मीडिया से चर्चा की। पटवारी ने कहा कि अब थानों के काम क्या बचे हैं जो टीआई है उनका काम है कि उस क्षेत्र में जुआ, सट्टा कैसे सुरक्षित चले? यह थाने का काम है कि कैसे अवैध शराब बिके और शराब के जितने भी डीलर और शराब के ठेकेदार हैं उनकी सुरक्षा कैसे हो यह पुलिस वालों का काम बच गया है। पुलिस वालों का काम है कि नाइट क्लब जो रात में चलते हैं उनकी सुरक्षा कैसे हो? भोपाल में स्पा का एक कांड पकड़ा गया जिसमें 50-60 लड़के-लड़कियां पकड़े गए। वह थाने के पास में ही चल रहा था जितने भी अवैध काम है उनको चलाने के लिए टीआई को एक तरह से परमिट दे दिया। क्योंकि उस टीआई को पैसे लेकर ही थाना दिया गया था। वैसे ही वह पैसे लेकर वह काम करता है।

आदिवासियों के विद्रोह पर बनी फिल्म बीजेपी नेताओं को दिखाएंगे दिग्विजय सिंह

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह कांग्रेस और भाजपा के नेताओं को बैतूल के आदिवासियों के विद्रोह पर बनी फिल्म दिखाएंगे। 13 जनवरी को विधानसभा के मानसरोवर सभागार में फिल्म जंगल सत्याग्रह का प्रीमियर शो आयोजित किया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने इस शो के लिए कांग्रेस और भाजपा के विधायकों, सांसदों, पूर्व विधायकों और मंत्रियों समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं को निमंत्रण भेजा है। दिग्विजय सिंह खुद सीएम हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को इस फिल्म के प्रीमियर शो में आने का निमंत्रण दिया। दिग्विजय सिंह के पीएस सचिन वत्स और मीडिया कोऑर्डिनेटर योगेंद्र सिंह परिहार ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को भी निमंत्रण भेजा। साथ ही, मोहन सरकार के मंत्रियों और बीजेपी विधायकों को भी निमंत्रण भेजा जा रहा है।

गुप्टिल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा

» न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ने 14 साल के करियर को दिया विराम

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

वेलिंगटन। न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाजों में शामिल मार्टिन गुप्टिल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 38 साल के गुप्टिल ने 2009 में डेब्यू किया था और अपने 14 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर को समाप्त करने का आधिकारिक एलान किया। उन्होंने अक्तूबर 2022 में न्यूजीलैंड के लिए अपना अंतिम मुकाबला खेला था। गुप्टिल ने तीनों प्रारूप मिलाकर न्यूजीलैंड के लिए कुल 367 मैच खेले हैं।

गुप्टिल ने अपने करियर में 23 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाए और सीमित ओवरों के प्रारूप में अपना जलवा बिखेरा था। गुप्टिल न्यूजीलैंड के लिए टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 122 मैचों में 3531 रन बनाए हैं। वनडे में उन्होंने 7346 रन बनाए हैं और इस प्रारूप में वह न्यूजीलैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनसे आगे रॉस टेलर और स्टेफन फ्लेमिंग हैं। गुप्टिल न्यूजीलैंड के पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपने पहले वनडे मैच में शतक लगाया है। गुप्टिल ने अपने करियर में कई शानदार पारियां खेली हैं जिसमें 2015 विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली 237 रनों की रिकॉर्ड पारी है। यह विश्व कप में किसी बल्लेबाज का निजी सर्वोच्च स्कोर है और वह न्यूजीलैंड के पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने वनडे में दोहरा शतक लगाया है।

टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार जसप्रीत बुमराह

दुबई। जसप्रीत बुमराह की आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में बादशाहत कायम है और उन्होंने करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग 908 अंक हासिल कर ली है। दूसरी ओर, गेंदबाजों की रैंकिंग में स्पिनर रवींद्र जडेजा संयुक्त रूप से नौवें स्थान पर आ गए हैं और वह बुमराह के अलावा शीर्ष-10 में जगह बनाने वाले दूसरे गेंदबाज हैं। जडेजा के साथ नौवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड हैं जिन्होंने 29 स्थान की छलांग लगाई और शीर्ष-10 में पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के कैगिसो रबादा एक पायदान के लाभ से तीसरे स्थान पर पहुंचे, जबकि चोटिल जोश हेजलवुड दो पायदान के नुकसान से चौथे स्थान पर खिसक गए। वहीं ऋषभ पंत बल्लेबाजी रैंकिंग में तीन पायदान की छलांग लगाने में सफल रहे और नौवें नंबर पर पहुंच गए, जबकि भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अपना चौथा स्थान कायम रखा।

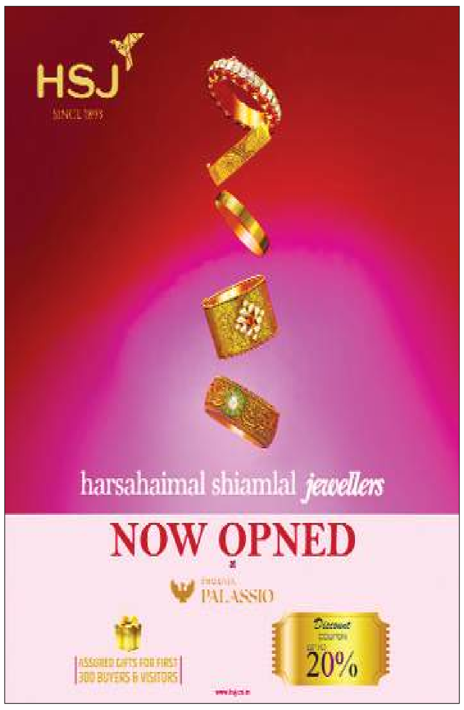

HSJ
harsahaimal shiamlal jewellers
NOW OPNED
PALASSIO
ASSURED GIFTS FOR FIRST 300 BUYERS & VISITORS
Discount
20%

फोटोः सुमित कुमार

छोटों पर सितम बड़ों पर रहम परिवहन विभाग के प्रवर्तन और ट्रैफिक पुलिस ने हजरतगंज में नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान दो पहिया व निजी वाहनों का जमकर चालान हुआ, कारवां बीजेपी कार्यालय तक पहुंचते-पहुंचते बिखर गया। यहां तक कि वहां अतिक्रमण रोधी दस्ते के सामने से ही ब्लैक फिल्म लगी सफारी निकली लेकिन उस गाड़ी पर दस्ते के मोबाइल का कैमरा नहीं घूमा, क्योंकि ब्लैक फिल्म वाली गाड़ी पर लगा था भाजपा का झंडा।

लोकतंत्र के नाम पर कलंकतंत्र बन गयी हैं सरकारी योजनाएं

पीएम मोदी पर पांच राज्यों ने लगाया भेदभाव का आरोप

» जिन राज्यों में नहीं है डबल इंजन की सरकार वहां केंद्र सरकार नहीं दे रही योजनाओं का पैसा

» ममता बनर्जी, सुक्खू आतिशी के बाद हेमंत सरकार भी केंद्र पर बरसी

» वृद्धा पेंशन, मनरेगा समेत दूसरी कई योजनाओं का करोड़ों रुपया केंद्र सरकार नहीं दे रही

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश के बाद केन्द्र सरकार पर बड़ा आरोप झारखंड सरकार लगा रही है। ताजा आरोपों के मुताबिक झारखंड को सरकारी योजनओं की मार्फत मिलने वाले फंड पर केन्द्र सरकार ने रोक लगा दी है और उसे पैसा नहीं मिल रहा है। इस तरह के आरोप इससे पहले ममता बनर्जी, आतिशी और सुक्खू कि सरकारें लगा चुकी है।

झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय ने कहा है कि बार-बार आग्रह करने के बाद भी केन्द्र सरकार मनरेगा सहित झारखंड सरकार की कई योजनाओं की राशि नही दे रही है। इस तरह के आरोप उन्य रज्यों से आ रहे हैं जहां डबल इंजन की सरकार नहीं बन पायी।

वित्तीय मदद देने में उदारता बरते केंद्र : अब्दुल्ला

जम्मू। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गत दिनों नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। जम्मू-कश्मीर के वित्त क्षेत्र पर चर्चा कर सीएम ने जम्मू-कश्मीर के लिए उदार निधि की मांग की। उन्होंने वित्त मंत्री से पिछले वित्तीय वर्ष की देनदारियों को कम करने के लिए यूटी को वित्तीय सहायता बढ़ाने पर जोर दिया। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री से बातचीत में मुख्यमंत्री ने 2023-24 में जमा होने वाली 10000 से 12000 करोड़ रुपये की देनदारियों को कम करने के लिए केंद्र से अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी है। उन्होंने वित्त मंत्री के साथ बजट-पूर्व चर्चा में क्षेत्र के लिए केंद्र से जरूरी सहायता मांगी। सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्री ने उमर को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उन्हें आश्वस्त किया गया है कि जम्मू कश्मीर की चिंताओं का समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री की केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात प्रशासनिक कार्यों की एक सतत प्रक्रिया है। 15 नवंबर को भी वित्त मंत्री से की थी मुलाकात बता दें, उमर ने गत 15 नवंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की थी। डेढ़ महीने के भीतर यह दूसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात में मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर में नए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए बहुपक्षीय वित्तपोषण का लाभ उठाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री से सहयोग मांगा था, जिसका उद्देश्य मौजूदा स्थानों पर भीड़भाड़ कम करना और इन नए चिह्नित स्थानों पर सुनियोजित और विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं मिल पा रही राशि !

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद रॉयल्टी के मद में झारखंड की बकाया राशि 1 लाख 36 हजार करोड़ को देने में किस तरह से आनाकानी की जा रही है यह सभी को पता है। मनरेगा के तहत झारखंड के केंद्र के पास 600 करोड़ रुपए बकाया हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारी मांग के अनुसार आवंटन नहीं हुआ तो राज्य सरकार को अपने दम पर अबुआ आवास की योजना लानी पड़ी। मंत्री ने कहा कि हमने केंद्र सरकार से आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि को बढ़ाने की मांग की है। वर्तमान में 1.20 लाख रुपए प्रति आवास निर्धारित है। हमारी मांग है कि केंद्र सरकार इस राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए करे। जिससे हर आवास में रसोईघर के साथ शौचालय भी बनाया जा सके। केंद्र सरकार को झारखंड की ओर से संचालित अबुआ आवास को मॉडल मानकर पूरे देशभर में अपनाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को बताना चाहिए 2022 से 2024 के बीच आखिर हमें आवास योजनाओं से क्यों दूर रखा गया? इसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले 1.25 लाख आवास देकर कोरम पूरा किया गया।

कर्ज के मर्ज में जकड़ी राजस्थान सरकार चुकाना पड़ रहा 37 हजार करोड़ का ब्याज

» गहलोत-वसुंधरा के बाद भजनलाल की गाड़ी में उधार का तेल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

जयपुर। राजस्थान की डबल इंजन सरकार कर्ज की पटरी पर दौड़ रही है। वित्त वर्ष में ही सरकार दिसंबर तक करीब 50 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज ले चुकी है। सरकार पर कुल कर्ज का भार पांच लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को छूने वाला है। पिछले बजट में सरकार ने जो कर्ज के आंकड़े दिए थे, उनके अनुसार 31 मार्च 2024 तक ही राजस्थान पर कुल कर्ज लगभग 4 लाख 44 हजार करोड़ रुपए हो गया था। इसके बाद सरकार बोर्ड कॉरपोरेशन से लेकर अलग-अलग संस्थानों के माध्यम से बाजार से भारी कर्ज उठा चुकी है।

इतना ही नहीं इस सप्ताह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में वित्त विभाग ने बैंक ऑफ बड़ौदा तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र से एक एमओयू किया है। जिसके तहत बैंक ऑफ बड़ौदा अगले छह वर्षों यानी 31 मार्च 2030 तक, प्रति वर्ष 20 हजार करोड़ रूपये का ऋण प्रदान करेगा। वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रूपये का ऋण उपलब्ध कराएगा। कुल 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने के लिए भजनलाल शर्मा सरकार सहमत हो गई है। सरकार ने बैंकों को बताया है कि यह धनराशि राजस्थान सरकार की विभिन्न परियोजनाओं, विशेषकर आधारभूत ढांचा क्षेत्र जैसे बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा, सड़क, पेयजल और स्वच्छता के लिए उपयोग में ली जाएगी।

बोर्ड-कॉरपोरेशन पर 1 लाख 12 हजार करोड़ का उधार

कर्ज को लेकर यह चिंता कोरी नहीं है। पूर्व में आरबीआई ने वित्त विभाग को पत्र लिखकर तय लिमिट से ज्यादा कर्ज नहीं लेने की चेतावनी दी थी, क्योंकि वित्त वर्ष 2022-23 और 23-24 की चारों तिमाहियों में राजस्थान को कर्ज की जो लिमिट दी गई थी, उसे नजरअंदाज करते हुए वित्त (मार्गोपाय) विभाग के अफसरों ने बाजार के कर्ज उठा लिया। चेतावनी के बाद स्थिति सुधरनी चाहिए थी, लेकिन कर्ज के आंकड़ें चीख-चीख कर कह रहे हैं कि यह और ज्यादा बिगड़े हैं। मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार अपने टैक्स और नॉन टैक्स से मिलने वाले राजस्व के अतिरिक्त बाजार से लगभग 50 हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। सीएजी के ऑडिटेड आंकड़ों के अनुसार बोर्ड-कॉरपोरेशन पर मौजूदा समय में करीब 1 लाख 12 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है। इनमें से ज्यादातर बोर्ड-कॉरपोरेशन ऐसे हैं, जिनके पास कर्ज चुकाने के लिए आमदनी का कोई जरिया ही नहीं है।

फोटोः 4पीएम

औचक निरीक्षण मंडलायुक्त रोशन जैकब ने शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर आज डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम चौराहा, अटल चौराहा (जानकीपुरम) इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा व अटल चौक (हजरतगंज) का औचक निरीक्षण किया।

अखिलेश यादव के चाचा राजपाल सिंह का निधन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। सपा संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई राजपाल सिंह यादव का निधन हो गया है। गुरुवार तड़के चार बजे उनका निधन हुआ है। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे।

उनका गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली है। उनके निधन की खबर से यादव परिवार और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं अपने चाचा के निधन की जानकारी होने पर अखिलेश यादव भी सैफई के लिए रवाना हो चुके है।

मंदिर भगदड़ के बाद सीएम नायडू ने बुलाई समीक्षा बैठक

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

छह श्रद्धालुओं की हुई मौत, मृतकों के परिजनों से मिलने भी जाएंगे मुख्यमंत्री

हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स पर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में वैकुंठ एकादशी उत्सव शुरू होने से दो दिन पहले मची भगदड़ को लेकर राज्य सरकार सतर्क है।

घटना में छह श्रद्धालुओं की मौत बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने समीक्षा बैठक बुलाई है। साथ ही वह मृतकों के परिजनों से भी मिलने जाएंगे। तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम कुमार जैन ने कहा कि सरकार तिरुपति भगदड़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि तिरुमाला तिरुपति मंदिर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। मंदिर प्रशासन का दावा है कि भगदड़ में छह श्रद्धालुओं की जान चली गई और करीब 40 लोग घायल हो गए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने भी समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक के बाद वे भी थोड़ी देर में मंदिर जाएंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बैकुंठ एकादशी के अवसर पर लोग एकत्र हुए थे और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उचित व्यवस्था की गई थी। छह मृतकों में से एक महिला तमिलनाडु की बताई जा रही है और मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी।

स्वामी 4 पीएम न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक **संजय शर्मा** द्वारा आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित एवं 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। **महाराष्ट्र कार्यालय**:- 2 जी, कृष्णा कुटीर सागरिका CHS जुहू तारा रोड जुहू- मुंबई- 400049। **संपादक** - संजय शर्मा, **विधि सलाहकार**: सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, मोहम्मद हैदर, **वित्तीय सलाहकार**: संदीप बंसल, **कार्टूनिस्ट**: हसन जैदी, **दूरभाष**: 0522- 4078371 | **Email**: daily4pm@gmail.com |
website: www.4pm.co.in | **RNI-UPHIN/2015/62233** डाक पंजी. सं- SSP/LW/NP-495/2018-2020 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।